रजिस्ट्री सं० डी.(डी.)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 450] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 1979/कार्तिक 9, 1901
No. 450] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 190

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1979

का० आ० 624 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का 10) की धारा 9 के स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की बाबत, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित उच्च न्यायालय को, ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति के निरोध के प्रत्येक मामले के लिए, समुचित उच्च न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है ।

सारणी

संघ राज्यक्षेत्र	उच्च न्यायालय
1	2
अण्डमान और निकोबार द्वीप	कलकत्ता उच्च न्यायालय
अरुणाचल प्रदेश	गौहाटी उच्च न्यायालय
चण्डीगढ़	हरियाणा उच्च न्यायालय
दादरा और नागर हवेली	मुम्बई उच्च न्यायालय
गोआ, दमण और दीव	मुम्बई उच्च न्यायालय
लक्षद्वीप	केरल उच्च न्यायालय
मिजोरम	गौहाटी उच्च न्यायालय
पाण्डिचेरी	मद्रास उच्च न्यायालय

[फा० सं० 11(3)/79-ई सी० आर]

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 31st October, 1979

S.O. 624(E)—In exercise of the powers conferred by clause (c) of the Explanation to section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Ordinance, 1979 (10 of 1979), the Central Government hereby specifies with respect to each Union territory mentioned in column 1 of the Table below, the High Court mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Table as the appropriate High Court in every case of the detention of a person in pursuance of an order of detention made by the administrator of such Union territory or an Officer subordinate, to such administrator.

TABLE

Union territory	High Court
1	2
The Andaman and Nicobar Islands	Calcutta High Court
Arunachal Pradesh	Gauhati High Court
Chandigarh	Punjab and Haryana High Court
Dadra and Nagar Haveli	Bombay High Court
Goa, Daman and Diu	Bombay High Court
Lakshadweep	Kerala High Court
Mizoram	Gauhati High Court
Pondicherry	Madras High Court

[File No. 11 (3)/79-ECR]

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979